RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 221
दि. 12.12.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

देशभर में मतदाता सत्यापन की रफ्तार बढ़ी, चुनाव आयोग ने छह राज्यों में बढ़ाई SIR की समयसीमा अंतिम वोटर सूची अब 14 फरवरी को जारी होगी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में मतदाता सूची के सबसे बड़े अभियान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। आयोग ने यूपी समेत छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फॉर्म भरने की समयसीमा बढ़ाकर पूरे अभियान को नई गति देने का प्रयास किया है। पहले 11 दिसंबर को खत्म होने वाली यह अवधि अब अलग–अलग राज्यों के लिए नई तिथियों तक बढ़ा दी गई है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान–निकोबार में नागरिक अब 18 दिसंबर तक अपने फॉर्म भर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में यह सुविधा 26 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी, जबकि गुजरात और तमिलनाडु के लिए 14 दिसंबर की अंतिम तिथि तय की गई है। आयोग का मानना है कि कई जिलों से प्राप्त रिपोर्टों में अधिक भीड़, लंबित आवेदन और सटीकता के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत सामने आई, इसलिए यह विस्तार अनिवार्य था।

देश के बाकी हिस्सों में प्रक्रिया का पहिया अपनी गति से घूमता रहेगा। गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में निर्धारित समयसीमा गुरुवार को पूरी हो गई और अब इन राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित होगी। केरल में पहले ही समय 18 दिसंबर तक बढ़ाया जा चुका है, जिसकी ड्राफ्ट लिस्ट 23 दिसंबर को जारी होगी।

इससे पहले चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को भी SIR की अवधि एक सप्ताह बढ़ाई थी। उसी दौरान यह भी तय हुआ कि अंतिम मतदाता सूची अब 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी, जबकि पहले यह तारीख दिसंबर निर्धारित थी। आयोग का कहना है कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करना उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए मतदाता जोड़ने और हटाने की समयावधि 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई थी। ड्राफ्ट लिस्ट, जो पहले 9 दिसंबर को जारी होनी थी, अब 16 दिसंबर को आएगी।

इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई—देश में अब तक 99.24 प्रतिशत जनगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। डिजिटल प्रोसेस में मिली 2.91 करोड़ प्रविष्टियों को "अपुष्ट" श्रेणी में रखा गया है। इनमें वे मतदाता शामिल हैं जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, वे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, डुप्लिकेट नाम, फॉर्म वापस न करने वाले लोग और वे मतदाता जो लंबे समय से अनुपस्थित हैं। आयोग का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक साफ, सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए की जा रही है।

देश की चुनावी प्रणाली लगातार बड़े बदलावों से गुजर रही है और SIR का यह विस्तारित चरण उसी दिशा में एक और बड़ा कदम है। आयोग का दावा है कि अतिरिक्त समय मिलने से अधिक नागरिक अपनी प्रविष्टियों को सुधार सकेंगे, नए मतदाता जुड़ सकेंगे और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक मजबूत होगी।

पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पूर्व आईएसआई चीफ को सजा, फैज हमीद को 14 साल की कैद सैन्य सत्ता की कड़ी कार्रवाई से हिला इस्लामाबाद

(जीएनएस)। इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सेना की पकड़ और सियासी हलचल के बीच गुरुवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब देश की सैन्य अदालत ने पहली बार किसी पूर्व आईएसआई चीफ को कठोर सजा सुनाई। लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) फैज हमीद, जिन्हें कभी पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में सबसे प्रभावशाली प्रवर्तक माना जाता था, अब अगले 14 साल जेल में बिताएंगे। आईएसपीआर यानी पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने आधिकारिक रूप से पुष्टि करते हुए बताया कि फैज हमीद को सैन्य कानूनों के गंभीर उल्लंघन, आधिकारिक गोपनीयता का हनन और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे आरोपों में दोषी पाया गया है। पतन की यह कहानी पाकिस्तान की राजनीति और सैन्य ठिकानों में भूचाल की तरह देखी जा रही है।

इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत अगस्त 2024 में हुई थी। करीब 15 महीने तक चले कोर्ट मार्शल में उन्हें कई गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा—ऐसे आरोप जो आज तक सेना की शीर्ष पंक्ति के अधिकारियों पर खुले तौर पर नहीं लगाए जाते थे।

फैज पर आरोप था कि उन्होंने सेना के भीतर रहते हुए न सिर्फ राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया बल्कि संवेदनशील गोपनीय सूचनाओं का दुरुपयोग भी किया। बता गया कि उन्होंने अपने पद और संसाधनों का अनुचित इस्तेमाल कर व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों को बढ़ावा दिया। कोर्ट ने सभी आरोपों में उन्हें दोषी ठहराया, हालांकि कानून के मुताबिक उन्हें फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया गया है।

फैज हमीद का नाम पाकिस्तान की राजनीति में अचानक नहीं उभरा था। वह उन गिने–चुने सैन्य अधिकारियों में से थे जो सत्ता के असली केंद्र माने जाते रहे। 2019 से 2021 तक आईएसआई के डायरेक्टर जनरल रहते हुए वह तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के बेहद करीबी समझे जाते थे। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उनकी नियुक्तियों और फैसलों का असर न सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष की रणनीतियों पर भी पड़ता था।

चकवाल जिले के लतीफाल गांव में जन्मे फैज हमीद ने 1987 में पाकिस्तान मिलिट्री अकैडमी से करियर की शुरुआत की थी। धीरे–धीरे वह सेना के उन प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए जिनके निर्णय पाकिस्तान की राजनीति को दिशा देते रहे। आईएसआई के बाद वे पेशावर कोर के कमांडर भी बने, जिसे पाकिस्तान की सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पोस्ट माना जाता है।

लेकिन सत्ता के इस तेज सफर का अंत उतनी ही तेजी से हुआ। इमरान खान और सेना के बीच बढ़ती दूरी और उसके बाद बदले राजनीतिक माहौल में फैज हमीद की भूमिका पर सवाल उठने लगे। आरोप बढ़ते गए और आखिरकार पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में पहली बार किसी पूर्व आईएसआई चीफ का कोर्ट मार्शल कर उसे जेल भेज दिया गया।

इस फैसले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे सेना के भीतर अनुशासन स्थापित करने की बड़ी पहल बता रहे हैं, तो कुछ इसे पाकिस्तान की बदलती सत्ता संरचना का संकेत मान रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है—

फैज हमीद की सजा ने पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया है जिसकी गूंज आने वाले कई वर्षों तक सुनाई देगी।

कर्नाटक में जाति पंचायतों की मनमानी पर कानूनी नकेल - सामाजिक बहिष्कार को अब अपराध, हुक्का–पानी बंद करने वालों को होगी जेल

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक की विधानसभा में गुरुवार का दिन सामाजिक चेतना और संवैधानिक अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में दर्ज हो गया। सदियों से कई समुदायों में प्रचलित जाति पंचायतों की मनमानी, किसी व्यक्ति या परिवार का हुक्का–पानी बंद करना, सामाजिक बहिष्कार करना, उसे रिश्तेदारी, व्यापार, रोजगार या सामाजिक कार्यक्रमों से काट देना — अब कर्नाटक में यह सब अपराध की श्रेणी में आएगा। राज्य सरकार ने 'कर्नाटक सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध और निवारण) विधेयक, 2025' पेश किया है, जो ऐसे गैर-कानूनी आदेशों को न केवल निरस्त करता है, बल्कि दोषियों को तीन साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी दे सकता है।

यह विधेयक समाज कल्याण मंत्री एच. सी. महादेवप्पा द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया। इसमें सामाजिक बहिष्कार के 20 विभिन्न रूपों को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है ताकि कोई भी जातिगत या सामुदायिक संस्था कानून के बाहर जाकर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन न कर सके।

विधेयक में कहा गया है कि सामाजिक बहिष्कार के ये परंपरागत रूप — किसी के साथ लेन-देन रोक देना, उसके लिए काम करने से मना करना, उसकी दुकान, सेवा या व्यवसाय का बहिष्कार करना, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से रोकना, रिश्ते तोड़ने के फरमान, सार्वजनिक स्थल या सुविधाओं से दूर रखना — इन सभी का व्यक्तियों और परिवारों के जीवन पर गहरा, कभी–कभी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ऐसे फैसले अक्सर जाति पंचायतों या सामाजिक समूहों द्वारा बिना किसी संवैधानिक अधिकार के सुनाए जाते रहे हैं, जिससे पीड़ित और उनके परिवार समाज में अपमान, अकेलेपन, आर्थिक संकट और मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं। विधेयक स्पष्ट करता है कि ऐसे बहिष्कार न केवल मानव गरिमा के विरुद्ध हैं बल्कि भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों — समानता, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार — का भी उल्लंघन करते हैं। सरकार का कहना है कि इन प्रथाओं को जड़ से समाप्त करना आवश्यक है ताकि नागरिक बिना डर, बिना भेदभाव और बिना किसी सामुदायिक दबाव के गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

इसी सत्र में सरकार ने दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक — 'बृहत बेंगलुरु शासन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025' भी पेश किया। इसके अनुसार लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के जनप्रतिनिधियों को 'ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी' का सदस्य बनाया जाएगा।

चार लाख वर्ष पुरानी आग ने बदला मानव इतिहास का गणित - सफोक की धरती से मिला चौंकाने वाला पुरातात्विक सबूत

(जीएनएस)। सफोक, इंग्लैंड। मानव सभ्यता जिस आग पर आज तक निर्भर है, उसे नियंत्रित करने की क्षमता इंसानों ने कब हासिल की—यह सवाल हमेशा विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में रहा है। लंबे समय तक माना जाता रहा कि आग जलाने की तकनीक लगभग 50 हजार वर्ष पहले विकसित हुई होगी। लेकिन इंग्लैंड के सफोक स्थित बार्नहम पुरातात्विक स्थल पर मिली नवीनतम खोज ने इतिहास की इस समझ को पूरी तरह उलट दिया है। ब्रिटिश म्यूजियम और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की संयुक्त टीम को ऐसे प्रमाण मिले हैं, जो बताते हैं कि मानव जाति के पूर्वजों ने करीब 4 लाख वर्ष पहले ही आग जलाना सीख लिया था। यह खोज मानव विकास के इतिहास को लगभग साढ़े तीन लाख वर्ष पीछे ले जाती है और यह बताती है कि आग का आविष्कार मानव बुद्धिमत्ता के विकास का आरंभिक, निर्णायक क्षण था।

सबसे अहम तथ्य यह है कि ये प्रमाण निएंडरथल्स से जुड़े हैं—वे प्रारंभिक मानव जो उस समय यूरोप में रहते थे और जिन्हें अक्सर हमारे मुकाबले कम विकसित माना जाता रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि निएंडरथल्स न केवल उपकरण बनाना जानते थे, बल्कि आग जलाने और नियंत्रित करने में भी कुशल थे। यह क्षमता न केवल उनके दैनिक जीवन को बदलती थी बल्कि उनके सामाजिक ढांचे और भोजन प्रणाली को भी व्यापक रूप से प्रभावित करती थी।

बार्नहम साइट पर वैज्ञानिकों को लाल रंग की मिट्टी का एक विशाल धब्बा मिला, जो सिर्फ तभी बन सकता है जब मिट्टी को 700 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान पर कई बार गर्म किया जाए। इसके साथ मिली हाथ की कुल्हाड़ियाँ आग की ऊष्मा से फट चुकी थीं। यह स्पष्ट था कि यह सब किसी प्राकृतिक आग का प्रभाव नहीं, बल्कि सुनियोजित, नियंत्रित जलन का परिणाम था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अब तक का सबसे ठोस, सबसे पुराना वैज्ञानिक प्रमाण है जो यह साबित करता है कि आग सिर्फ उपयोग नहीं, बल्कि उत्पन्न की गई थी।

अब तक के प्रमाण बताते थे कि शुरुआती मानव समूह प्राकृतिक आग का उपयोग करते थे—बिजली गिरने या जंगलों में प्राकृतिक दहन के बाद बची लपटों को वे संभालकर रखते थे। लेकिन स्वयं आग पैदा करने का प्रचलन कब शुरू हुआ, यह स्पष्ट नहीं था। यह खोज न केवल इस प्रश्न का उत्तर देती है बल्कि मानव विकास की समयरेखा को पूरी तरह नए सिरे से समझने की आवश्यकता उत्पन्न करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि 4 लाख वर्ष पुराने स्थलों पर इतनी सटीक जांच से आग के प्रमाण मिल सकते हैं, तो भविष्य में 5 लाख वर्ष या उससे भी अधिक पुराने स्थलों पर इसी तरह के सूक्ष्म संकेत खोजे जा सकते हैं।

अरुणाचल की खामोश घाटी में मौत की गूंज : 1000 फीट की खाई, 21 जीवन और एक बचने की अद्भुत कहानी

(जीएनएस)। अरुणाचल प्रदेश के अनजॉ जिले की वो रात बिल्कुल सामान्य थी—पहाड़ियों के ऊपर ठंडी हवा बह रही थी, नीचे घने जंगलों में अंधेरा एक काली चादर की तरह पसरा था। हयुलियांग–चगलगाम रोड पर एक ट्रक धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। उसमें ड्राइवर, क्लीनर और अलग-अलग राज्यों से आए 19 मजदूर सवार थे, जो सड़क निर्माण कार्य से लौट रहे थे। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद पूरी घाटी एक ऐसी ख़ामोशी ओढ़ लेगी, जिसके पीछे 21 बेजुबान जानों की चीखें दबी होंगी। रात करीब साढ़े दस बजे अचानक पहाड़ी मोड़ पर ट्रक का संतुलन बिगड़ा। सड़क बेहद तंग थी, दाईं ओर 1000 फीट गहरी खाई, नीचे अंधेरे में गायब होती गहराई और ऊपर खड़ी चट्टानें। ट्रक कुछ सेकंड डगमगाया और फिर पहियों ने ज़मीन छोड़ी। भारी वाहन नीचे गिरते हुए पेड़ों और चट्टानों से टकराता चला गया। धातु के टूटने की आवाजें, चीखें और फिर सन्नाटा—सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। लेकिन उस सन्नाटे में एक आदमी की सांसें अभी भी चल रही थीं। वह मजदूर, जिसका नाम फिलहाल प्रशासन ने गुप्त रखा है, किसी तरह टुकड़ों के बीच फंसे ट्रक से बाहर निकल आया। उसका शरीर लहूलुहान था, पैर कांप रहे थे, लेकिन ज़िंदा रहने की जिद उसकी आंखों में चमक रही थी। वह खाई की खतरनाक ढलान पर रेंगता, घसीटता हुआ ऊपर चढ़ा। घने जंगलों में जंगली जानवरों की आवाजें थीं, रात में पाला जमने की ठंड थी, पर वह चलता रहा।

दो दिन और दो रात उसने बिना भोजन-पानी के पहाड़ियों के बीच सफर तय किया। कभी ज़मीन पर गिर जाता, कभी पत्थरों का सहारा लेकर उठता। और आखिरकार, 10 दिसंबर की रात वह चिपरा GREF कैंप के बाहर गिर पड़ा। जवानों ने उसकी हालत देखकर उसे अंदर ले जाया। जब उसने अपनी टूटी हुई आवाज में कहा—"साहब ट्रक सब खाई में गिर गए"—तो पूरे कैंप में हलचल मच गई।

सुबह होते ही सेना, GREF और मेडिकल टीमों का रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ। हादसे वाली जगह चगलगाम से 12 किलोमीटर अंदर, घने जंगल और तेज ढलानों के बीच थी। टीम को वहां पहुंचने में ही 10 घंटे लग गए। खाई इतनी गहरी और झाड़ियां इतनी घनी थीं कि ट्रक दिखाई भी नहीं दे रहा था। रस्सियों के सहारे जवान नीचे उतरे। चार घंटे की तलाश के बाद मलबे के बीच ट्रक की धातु की पत्ती चमकी—और फिर शुरू हुई मौत की गिनती। 18 शव बरामद किए गए, जिन्हें बेले रोप्स के सहारे ऊपर खींचा जा रहा है। कई शव पेड़ों में फंसे हुए मिले, कुछ चट्टानों के बीच। बचाव कार्य अभी जारी है। जिला प्रशासन, NDRF, GREF, पुलिस—सब मिलकर शवों की पहचान में लगे हुए हैं। ADC हायुलियांग ने बताया कि ठेकेदारों और स्थानीय प्रतिनिधियों से मजदूरों की पूरी सूची हासिल करने की कोशिश की जा रही है।

राष्ट्रीय एकता का वाहक बने स्वतंत्रता का अस्त्र

'बेकार की बहस मत करो' यह पांच शब्द शायद ही किसी ने न सुनें या न बोले होंगे। इस बहस का सीधा-सा मतलब किसी विवादास्पद विषय पर विचार-विमर्श करके एक स्वीकार्य नतीजे पर पहुंचना होता है। हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था में संसद अथवा विधानसभाओं में जब बहस की जाती है तो इसके मूल में कोई ऐसा विषय होता है जो विवादास्पद हो, जिस पर विचार करने वालों में विवाद हो। तब विषय पर संवाद करके किसी एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। लेकिन, जब विवाद की स्थिति ही न हो, किसी विषय पर मतभेद हो ही नहीं तो फिर बहस क्यों? उस दिन जब संसद में हमारे 'राष्ट्रीय गीत' को लेकर बहस हो रही थी तो एक सवाल बार-बार मन में उठ रहा था यह बहस हो क्यों रही है? 'वंदे मातरम्' हमारी आज़ादी की लड़ाई का महामंत्र था, हमारे पूर्वजों ने इस मंत्र को हथियार बनाकर यह लड़ाई जीती थी। फिर जब संविधान-सभा में राष्ट्रगान को लेकर विचार हो रहा था तो सदस्यों ने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचना 'जन-गण-मन' को 'राष्ट्रगान' के रूप में स्वीकारा और बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना 'वंदे मातरम्' के प्रारंभिक अंश को 'राष्ट्रगीत' की मान्यता दी गयी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी यह राष्ट्रगीत गाया जाता था और बाद में भी इसे राष्ट्रगान के समकक्ष ही सम्मान दिया गया। आज़ादी की लड़ाई का साझा मंच थी कांग्रेस। कांग्रेस के हर अधिवेशन में तब

भी, और अब भी, इसे पूरे सम्मान के साथ गाया जाता है। फिर 'बहस' किस बात की है?

आज से डेढ़ सौ साल पहले, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना की थी, जिसे बाद में उन्होंने अपने उपन्यास 'आनंदमठ' में भी जोड़ा। देखते ही देखते यह 'वंदे मातरम्' हमारी आज़ादी की लड़ाई का महामंत्र बन गया। इस मंत्र की शक्ति और लोकप्रियता ने अंग्रेज़ों को दहला दिया था। उन्होंने इस 'जयघोष' पर ही प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध ने इसे और ताकतवर बनाया। कोड़े बरसते रहे, वंदे मातरम् का जयघोष गूंजता रहा। डेढ़ सौ साल पहले लगा यह जयघोष आज भी उतना ही ताकतवर और महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है यह जानना कि 'जन गण मन' को राष्ट्रगान और 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगीत घोषित करके इस बारे में भ्रम के इस अध्याय को समाप्त कर दिया गया था। इसीलिए वंदे मातरम् की महान रचना का 150वां साल मनाना तो समझ में आता है, पर इस पर 'बहस' किस बात की? इस 'बहस' की मांग सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से की गयी थी। होना तो यह चाहिए था कि इस अवसर का उपयोग उन स्वतंत्रता- सेनानियों को श्रद्धांजलि देकर उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन के लिए किया जाता; यह संकल्प लिया जाता कि हम उन सेनानियों के बलिदान को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे; उनके सपनों को साकार करने का हरसंभव प्रयास करेंगे। पर हुआ यह कि संसद में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे सांसदों ने इसे राजनीतिक लाभ उठाने का अवसर बना दिया! यह अवसर मिल-जुल कर उत्सव मनाने का था, दुर्भाग्य ही है कि हमारे नेताओं ने इसे एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने तक ही सीमित करके रख दिया। अवसर था कि हमारे नेता इस राष्ट्रगीत की महत्ता समझाते, यह बताते कि कैसे इस गीत के दो शब्दों 'वंदे मातरम्' ने देश में आज़ादी की लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ला पहुंचाया था। यह अवसर था कि देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति समर्पण का अहसास कराया जाता। यह अवसर था कि भावी पीढ़ियों के लिए इस आशय का संदेश छोड़ा जाता कि कैसे सारा देश डेढ़ सौ साल पहले एक गीत के माध्यम से एकजुट हो गया था। पर संसद में हुई 'बहस' में ऐसा कुछ नहीं दिखा–दिखा तो सिर्फ यह कि राजनेता राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना ही नहीं चाहते। सत्तारूढ़ पक्ष सारा समय यही शिकायत करता रहा कि गीत के टुकड़े करके देश को तोड़ दिया गया और विपक्ष यही बताता रहा कि कैसे सत्तारूढ़ पक्ष के पूर्वजों ने अंग्रेजों का साथ देकर आज़ादी की लड़ाई के साथ 'विश्वासघात' किया था! पता नहीं, प्रधानमंत्री ने बहस की शुरुआत करते हुए यह कहना ज़रूरी क्यों समझा कि वंदे मातरम् गीत के टुकड़े करके जवाहरलाल नेहरू ने गीत की आत्मा को कमज़ोर बना दिया। उन्होंने यह कहना भी ज़रूरी समझा कि गीत के कुछ हिस्से हटाने से इस निर्णय ने देश के बंटवारे के बीज बो दिये थे। इतिहास साक्षी है कि 'आनंदमठ' में दिये गये लंबे गीत को 'राष्ट्रगीत' बनाने के लिए उसे कुछ संक्षिप्त करने का निर्णय जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, कांग्रेस की एक समिति ने लिया था और इस समिति में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू जैसे अन्य लोग भी थे। हकीकत यह भी है कि गीत को संक्षिप्त करने का निर्णय लेने से पहले गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर से भी परामर्श किया गया था और उन्होंने भी इस निर्णय से सहमति व्यक्त की थी।

बंगाल में चिंतित करने वाला घटनाक्रम, बाबर के नाम से मस्जिद बनाना करोड़ों हिंदुओं सिखों की भावनाओं को चोट पहुंचाना

इस तस्वीर की हमने शायद ही कल्पना की हो कि देश में कहीं पर फिर से बाबरी मस्जिद की नींव डाली जाएगी और उसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा इलाके में प्रतीकात्मक तौर पर फीता काटकर मस्जिद की नींव रख दी। हुमायूं कबीर पश्चिम मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर से विधायक हैं। वे लंबे समय से सार्वजनिक वक्तव्य दे रहे थे कि छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत करेंगे। इस कारण बंगाल के अंदर और देश में असहजता का माहौल कायम हो रहा था। अलग-अलग मंचों से इसे रोकने की मांग भी की गई, किंतु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। केवल हुमायूं कबीर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

कानून-व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कोई भी राज्य सांप्रदायिकता भड़काने और तनाव फैलाने की योजना वाले हुमायूं कबीर जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता, हिरासत में लेता या कम से कम उसे नजरबंद करता। इसके साथ ऐसे कार्यक्रम पर रोक भी लगाता। मुर्शिदाबाद का दृश्य इसके विपरीत था। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस उस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए वहां तैनात है। जब पुलिस-प्रशासन को राजनीतिक नेतृत्व से रोकने का कोई आदेश नहीं था तो वह ऐसी ही भूमिका निभाएगा। किसी को भी कानूनी रूप से वैध जमीन पर मंदिर या मस्जिद बनाने का अधिकार है, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद बनाना करोड़ों हिंदुओं-सिखों की भावनाओं को चोट पहुंचाना और उनके जख्मों को कुरेदना है। यह हर दृष्टि से अस्वीकार्य है। 1529 में बाबर के सेनापति मीर बकी द्वारा अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद निर्माण के विरुद्ध वर्षों का संघर्ष अब सबको पता है। अंततः स्वतंत्रता के बाद आंदोलन और फिर आगे न्यायिक संघर्ष से उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर निर्माण किया गया। बावजूद इसके देश का एक वर्ग मानता है कि बाबर के साथ उसका जुड़ाव है, उससे प्रेरणा मिलती है और इसलिए उसके नाम की मस्जिद बनानी है। यह भारत की एकता-अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से अशुभ संकेत है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जिस बाबर को उसके मूल स्थान के कई इतिहासकार लुटेरा कहते हैं, अनेक भारतीय मुसलमान स्वयं को उससे जोड़ते हैं? हुमायूं कबीर के बाद तहरीक मुस्लिम शब्बन नामक संगठन ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने का एलान किया है। पता नहीं आगे कौन कहां बाबर के नाम पर और कुछ निर्माण की घोषणा कर दे। भारत विभाजन के पीछे बंगाल वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप से कट्टरपंथियों के लिए बहुत बड़ी ताकत बना था। 16 अगस्त, 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यहीं हुआ था, जिसमें कई सौ हिंदुओं को मारा गया था, ताकि गैर मुस्लिम डर जाएं और कांग्रेस दबाव में आए एवं ब्रिटिश सरकार के सामने मुसलमानों को अलग देश देने के अलावा चारा न बचे।

आखिर हुमायूं कबीर के साथ मुस्लिम समुदाय के इतने लोगों के खड़े होने, रुपये देने का विश्लेषण कोई कैसे करेगा? कुछ लोग इसे पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देख सकते हैं। अगर हुमायूं कबीर को बाबर के नाम पर वोट मिलने की उम्मीद है तो इससे खतरनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। हुमायूं कबीर की सांप्रदायिक और हिंदू विरोधी मानसिकता लंबे समय से सामने है। मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद में 70 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम है। भाजपा के समर्थकों को भागीरथी नदी में फेंक देंगे। आखिर मुर्शिदाबाद में भाजपा के समर्थक किस समुदाय के हैं?

इसी वर्ष अप्रैल में मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के बहाने हुई हिंसा को याद करिए और हुमायूं कबीर के इस बयान को देखिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित तथ्य खोजी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यहां की हिंसा पर दिल दहलाने वाले बातें कही थीं। उसमें कहा गया था कि हिंसा केवल हिंदुओं के विरुद्ध थी और सुनियोजित थी तथा स्थानीय तृणमूल के मुस्लिम नेता और पार्षद ने हिंसा का नेतृत्व किया। यह भी कि लोगों ने पुलिस से मदद मांगी, पर पुलिस ने न हिंसा रोकने की कोशिश की और न पीड़ितों को सुरक्षा देने की ही। इस घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले बीएसएफ पर आरोप लगाया और फिर बाद में इसे भाजपा और संघ की साजिश करार देती रहीं।

पहले बंगाल के वामपंथी नेताओं और अब ममता ने ऐसे खतरनाक कट्टर हिंसक शेर की सवारी की है, जो उनके लिए भी संकट बन रहा है और देश के लिए भी। किसी भी समुदाय से उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर इतिहास की कुछ बातें स्पष्ट हैं तो उन्हें स्वीकार कर दूसरों की भावनाओं का सम्मान करे। भारत में दृश्य इसके उलट हैं। यहां बाबर का खुलेआम गुणगान हो रहा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव के बाद देश को इस्लामी कट्टरवाद के कटु यथार्थ को समझना चाहिए और सरकार के साथ आम लोगों को भी सोचना चाहिए कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए? मुस्लिम समुदाय के अंदर भी ऐसे लोग हैं, जो इस प्रकार के व्यवहार को उचित नहीं मानते। उन्हें भी आगे आकर विरोध करना पड़ेगा।

आत्मनिर्भर बनने का सही रास्ता, भारत बनेगा वैश्विक आर्थिक महाशक्ति

बीते दिनों जब दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से भेंट की थी तो उन्होंने इस भेंट को जी-2 का नाम दिया था। यानी उन्होंने एक तरह से मान लिया कि अमेरिका के बाद चीन दूसरी विश्व महाशक्ति बन चुका है, जिसे रोकना अब उसके वश की बात नहीं है और सोवियत संघ के विघटन के बाद एकध्रुवीय विश्व अब फिर से द्विध्रुवीय है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप चीन को सबक सिखाने की बातें किया करते थे, पर अब उनके सुर पूरी तरह बदल चुके हैं।

वैसे ट्रंप इस वार्ता से पहले ही चीनी उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की योजना को एक साल के लिए स्थगित कर चुके थे। फिलहाल चीनी उत्पादों पर अमेरिका 47 प्रतिशत का ही टैरिफ लगा रहा है। भारत जिसके साथ सामरिक साझेदारी को अमेरिकी नेता पिछले दो दशक से 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बताते नहीं थकते, उसके उत्पादों पर 50 प्रतिशत का टैरिफ है, जबकि अमेरिका अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी देश चीन पर उससे कम टैरिफ लगा रहा है।

ट्रंप से जब ताइवान पर चीनी हमले के खतरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह जब होगा, तब देखेंगे। ट्रंप ने यह नहीं कहा कि वे ट्रेड डील का भय दिखाकर ताइवान को चीनी हमले से बचा लेंगे। इससे उलट ट्रंप हर तीन-चार दिन में भारत को लज्जित करने के लिए आपरेशन सिंदूर रुकवाने का झूठा दावा यह कहकर करते हैं कि उन्होंने व्यापारिक समझौता न करने का भय दिखाकर संभावित परमाणु युद्ध रुकवा दिया। रूस से कच्चा तेल भारत और चीन, दोनों ही आयात कर रहे हैं, पर ट्रंप प्रशासन हाथ धोकर भारत के ही पीछे पड़ा है। इस सबसे समझा जा सकता है कि चीन के सामने नतमस्तक अमेरिकी शासन तंत्र ने अब यह ठाना है कि अगर चीन विश्व की दूसरी महाशक्ति बन ही गया है और उसे रोकना उसके वश की बात नहीं रही है तो कम से कम भारत और रूस का उभार तो रोका ही जाए।

चीन की इस मजबूत स्थिति के पीछे उसकी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण तकनीक के अनुसंधान और उत्पादन में पहल करने की दशकों की नीति रही है। चीनी रणनीतिकारों ने ऐसे सेक्टरों और तकनीकी उत्पादों को चिह्नित किया, जिनके माध्यम से अमेरिका और विश्व को अपने ऊपर निर्भर बनाया जा सके। परिणामस्वरूप चीन आज ऐसे कई उत्पादों की आपूर्ति शृंखलाओं को नियंत्रित करता है और उनके माध्यम से उसने ट्रंप के टैरिफ युद्ध का मुंहतोड़ जवाब दिया है। ट्रंप ने चीन के उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी तो उसने अमेरिका को रेयर अर्थ मैगनेट्स की आपूर्ति रोक दी, जिससे अमेरिका का उद्योग जगत परेशान हो उठा और ट्रंप को टैरिफ लगाने की अपनी योजना को स्थगित करना पड़ा। दुर्लभ भूगर्भीय खनिज आज अंतरिक्ष यानों, रक्षा उपकरणों, इलेक्ट्रिक कारों से लेकर हेडफोन बनाने के लिए आवश्यक हैं और ये आवश्यक होंगी, यह चीन बहुत पहले पहचान चुका था।

चीन ने 1960 के दशक में ही इन दुर्लभ खनिजों के बारे में जानने-समझने के लिए अपने लोगों को अमेरिका भेजना प्रारंभ कर दिया था। 1970 के दशक में चीनी सरकार ने इन खनिजों का औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ कराया और 1980 के दशक में दुर्लभ खनिजों से जुड़े उद्योगों को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सेक्टर का दर्जा दे दिया। जिसके चलते इस सेक्टर को चीन में सरकारी सब्सिडी और निवेश मिलने लगा। इसका प्रभाव यह हुआ कि 1990 के दशक में ही चीन ने दुर्लभ खनिज उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। आज चीन विश्व के 85 प्रतिशत दुर्लभ खनिज शोध उद्योग को नियंत्रित करता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें अमेरिका और यूरोप आज चीन पर निर्भर हैं। चीन आज विश्व के 60 प्रतिशत सेमीकंडक्टर चिप्स, 75 प्रतिशत लिथियम बैटरियां, 80 प्रतिशत सोलर पैनल, 95 प्रतिशत पोलिसिलिकान वैफर बनाता है। भविष्य की क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए आवश्यक 60 प्रतिशत घटक चीन ने अभी से बनाने शुरू कर दिए हैं। इसलिए ट्रंप चीन के सामने नतमस्तक हैं। अमेरिका चीन पर प्रतिबंध लगा सकता है तो चीन भी जवाब में अमेरिका को ऐसी वस्तुओं का निर्यात रोक सकता है, जिनके चलते अमेरिका की अर्थव्यवस्था डूब सकती है।

इसकी तुलना में भारत के पास ऐसा क्या है, जो अमेरिका से सौदेबाजी के लिए उपयोग किया जा सके? हमने ऐसे कौन से सामरिक उद्योग विकसित किए हैं, जो विश्व को हम पर निर्भर बनाते हों? अमेरिका द्वारा आयात की जाने वाली जेनरिक दवाओं में से 25-30 प्रतिशत अवश्य भारत में बनती हैं, परंतु उनके लिए 60-75 प्रतिशत कच्चा माल या एपीआइ भारत चीन से आयात करता है। आर्थिक सुधारों के 35 वर्षों बाद यह बेहद शर्मनाक स्थिति है। चीन ने दुनिया को खुद पर निर्भर बनाने के लिए सामरिक सेक्टरों और तकनीकी में दशकों तक बिना लाभ की आकांक्षा किए निवेश किया है। भारत में न तो नेता ये करने को तैयार हैं और न ही उद्योगपति। उद्योगपति नई तकनीकों के विकास की जगह वस्तुओं और आमजन को सेवाएं देकर लाभ कमाने में व्यस्त हैं।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने महात्मा मंदिर में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ कराया

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- गुजरात ने टेक्नोलॉजी प्रेरित विकास में सदैव अग्रसरता बनाए रखी है
- एग्रीकल्चर, हेल्थ, गवर्नेंस, अर्बन-रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पर चिंतन-मंथन विकसित गुजरात@2047 के विजन में नया बल देगा

-: उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी :-

- एआई केवल एक क्षेत्र नहीं; बल्कि नई ऊर्जा है, जो प्रत्येक क्षेत्र को गति के साथ शक्ति दे रही है, गुजरात एआई क्रांति का केन्द्र बनेगा
- निवेशकों तथा एआई स्टार्टअप्स के लिए गुजरात प्लेटफॉर्म बनेगा, उज्ज्वल भविष्य के लिए लॉन्च पैड बनेगा

- **उप मुख्यमंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की उपस्थिति**
- **प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप में एआई राष्ट्रीय प्रगति का मिशन बना है : मुख्यमंत्री**
- **जन सुख-समृद्धि में वृद्धि, पारदर्शिता तथा फ्यूचर रेडी गुजरात के लिए एआई सक्षम संसाधन है : मुख्यमंत्री**
- **मुख्यमंत्री ने गुजरात यूनिफाइड डिजिटल स्टैक को ऑपरेशनलाइज्ड कर डिजिटल गवर्नेंस को अधिक स्मार्ट, तेज तथा सिटीजन सेंट्रिक बनाने की मंशा व्यक्त की**
- **'सुशासन' के लिए वर्तमान समय में एआई सबसे शक्तिशाली टूल्स के रूप में स्थापित : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया**
- **मुख्यमंत्री के करकमलों से 'गुजरात एआई स्टैक' की लॉन्चिंग तथा 'गुजरात क्लाउड एडॉप्शन गाइडलाइन्स 2025' का अनावरण किया गया**
- **गुजरात सरकार ने गूगल, भाषिणी, गिफ्ट सिटी तथा हेनोक्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए**

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यव्यापी गुजरात यूनिफाइड डिजिटल स्टैक को ऑपरेशनलाइज कर डिजिटल गवर्नेंस को अधिक स्मार्ट, तेज तथा सिटीजन सेंट्रिक बनाने की मंशा व्यक्त की है।

उन्होंने जोड़ा कि इसके परिणामस्वरूप नागरिकों को सभी सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म से आसानी से मिलने के साथ विभागों के बीच डेटा शेयरिंग तेज बनने से योजनाओं के आउटकम का रीयल टाइम एनालिसिस भी हो सकेगा।

श्री पटेल गुरुवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित हो रही रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ कराते हुए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस अंतर्गत आयोजित एआई एक्सपीरियंस जोन का उद्घाटन कर विभिन्न स्टार्टअप स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया उपस्थित रहे।

इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन केन्द्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपक्रम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में फरवरी-2026 में आयोजित होने वाली एआई इम्पैक्ट समिट के पूर्वार्ध तथा प्री-इवेंट के रूप में किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर गुजरात एआई स्टैक लॉन्च किया। इस एआई स्टैक के लॉन्च होने से सरकारी विभागों में 'प्लग-एंड-प्ले' एआई अपनाने के लिए 6 प्रमुख एआई टूल्स – कृषि एआई, योजना की पात्रता जाँच, प्रोक्योरमेंट चैटबोट, ग्रीवेंस क्लासीफायर, डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रैक्टर तथा चैट मैनेजमेंट टूल से गवर्नेंस अधिक तेज, सटीक तथा नागरिकोन्मुखी बनेगा।

गुजरात क्लाउड एडॉप्शन गाइडलाइन्स 2025 भी महानुभावों ने लॉन्च की। राज्य के डिजिटल गवर्नेंस को अधिक सुरक्षित, स्केलेबल तथा एआई रेडी बनाने के लिए ये गाइडलाइन्स 2025 में उपयोगी सिद्ध होंगी और Meity एम्पैनल्ड कम्प्यूट का उपयोग आसान बनेगा।

इस कॉन्फ्रेंस में दो महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें गुजरात सरकार - गूगल और भाषिणी के बीच हुए एमओयू के अनुसार बहुभाषीय एआई, गुजराती भाषा मॉडलों और डिजिटल पब्लिक सर्विसेज के लिए रणनीतिक भागीदारी की जाएगी।

इतना ही नहीं; गुजरात सरकार – गिफ्ट सिटी तथा हेनोक्स द्वारा राज्य में केबल लैंडिंग स्टेशन्स (सीएलएस) स्थापित करने के लिए एमओयू किया गया। इससे गुजरात वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी का केन्द्र बनेगा तथा ग्रीन डेटा सेंटर्स को बल प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री की लीडरशिप में एआई केवल टेक्नोलॉजी का संसाधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति का मिशन बन गया है। गुजरात ने सदैव टेक्नोलॉजी प्रेरित विकास में अग्रसरता बनाए रखी है। उन्होंने जोड़ा कि जन सुख-समृद्धि में वृद्धि, पारदर्शिता तथा फ्यूचर रेडी गुजरात के लिए एआई सक्षम संसाधन है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप में देश में गत एक दशक में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। छोटे से छोटे व्यक्ति तक टेक्नोलॉजी पहुँची है और इंडिया एआई मिशन शुरू हुआ है। गुजरात ने भी इसके अनुरूप रहकर टास्क फोर्स का गठन किया है।

उन्होंने अपेक्षा दर्शाई कि इस रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में होने वाला सामूहिक मंथन एआई के उपयोग द्वारा टेक्नोलॉजी की मदद से आज के कार्यों से आने वाले कल की क्षमता के दृष्टिकोण को बदलने में उपयोगी बनेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने गुजरात को एआई क्रांति का निर्माण करने वाला राज्य बताया और निवेशकों तथा एआई स्टार्टअप्स का गुजरात में स्वागत किया।

श्री संघवी ने कहा कि गुजरात सदैव 'अतिथि' तथा 'इनोवेशन' – इन दो शक्तिशाली परिबलों का स्वागत करता आया है। हमारा लक्ष्य ह्यूमन वर्सेज मशीन नहीं, बल्कि ह्यूमन विद मशीन है, जहाँ मानव कल्पना ने एक ऐसे पार्टनर का निर्माण किया है, जो कल्पना भी कर सकता है। एआई अब केवल एक क्षेत्र नहीं, बल्कि नई ऊर्जा है, जो प्रत्येक क्षेत्र को गति के साथ शक्ति दे रही है।

उन्होंने गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे एआई आधारित उपयोगों पर प्रकाश डालते हुए जोड़ा कि गिफ्ट सिटी में माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से स्थापित एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) भारत के आगामी टेक इकोसिस्टम को आकार दे रहा है। यह हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में गति दे रहा है। गुजरात में कृषि क्षेत्र में फसल एआई प्लेटफॉर्म द्वारा किसानों को पानी की बचत करने तथा कीटाणुनाशकों का उपयोग कम करने में मदद मिल रही है। कृषि प्रगति प्लेटफॉर्म पर एक लाख से अधिक किसानों को फसल के स्वास्थ्य, भूमि की स्थिति तथा जल की उपलब्धता के बारे में एआई आधारित सलाह मिल रही है, जो उनकी आय बढ़ाने में सहायक है। इसके अतिरिक्त; सिम्बा-एसआईएमबीए प्रोजेक्ट द्वारा वन्यजीवों की रक्षा की जा रही है। सार्वजनिक परिवहन सेवा जीएसआरटीसी में भी कार्यक्षमता सुधारने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। श्री संघवी ने गुजरात पुलिस द्वारा नागरिक सुरक्षा के लिए एआई टेक्नोलॉजी के किए गए उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अहमदाबाद में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथजी की रथयात्रा में पुलिस ने एआई सर्वेलांस के जरिए 5,481 गुमशुदा बच्चों को खोजकर उनका परिवार से पुनर्मिलन कराया। इतना ही नहीं, सुदूरवर्ती तथा ट्राइबल क्षेत्र माने जाने वाले दाहोद जिले में पुलिस ने अवैध गांजे की खेती के विरुद्ध राज्य का पहला एआई आधारित ऑपरेशन चलाया। मशीन-लर्निंग मॉडलों ने गांजे के पौधों को पहचाना और ड्रोन सर्वेलांस से 1.19 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का गांजा पकड़ा। इसके अलावा, अंबाजी मेले में एआई सर्वेलांस ने संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक कर गुमशुदा व्यक्तियों को खोजा तथा भीड़ प्रबंधन को मजबूत बनाया। श्री हर्ष संघवी ने सभी निवेशकों और एआई स्टार्टअप्स को गुजरात में निवेश करने, निर्माण करने तथा अपने सपने साकार करने के लिए आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, "गुजरात आपका प्लेटफॉर्म बनेगा। गुजरात आपके भविष्य का लॉन्च पैड बनेगा।" ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि सुशासन के लिए वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस – एआई सबसे शक्तिशाली टूल्स के रूप में स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात एआई क्षेत्र में अग्रसर रहा है। एआई के माध्यम से टेक्नोलॉजी, डेटा स्टोरेज, दैनिक कार्य में तेजी और पारदर्शिता आई है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों को घर बैठे सुविधा देने सहित विभिन्न सेवाओं में बड़ा परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत एआई तकनीक में नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। पुरानी और नई पीढ़ी रेडियो, टीवी, कंप्यूटर और अब एआई तकनीक क्षेत्र में आने वाले बदलाव की साक्षी बनी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात में आयोजित यह 'रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस' भविष्य में एआई क्षेत्र में नई क्रांति लाएगी। MeitY के अपर सचिव और एनआईसी के महानिदेशक श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशानिर्देशन में भारत में आगामी फरवरी 2026 में 'एआई इम्पैक्ट समिट' आयोजित होगी। विश्व में पहली बार किसी विकासशील देश में वैश्विक स्तर की एआई समिट आयोजित होगी। इस समिट को अधिक सार्थक बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक राज्य में भी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का आह्वान किया था, जिसके परिणामस्वरूप आज यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई टेक्नोलॉजी के क्रियान्वयन में गुजरात हमेशा देश में लीड लेकर अग्रसर रहा है। अब एआई के क्षेत्र में भी गुजरात देश के लिए रोल मॉडल बनेगा।

पश्चिम रेलवे ने मनाया सिविल डिफेन्स वार्षिक दिवस – 2025

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता द्वारा महालक्ष्मी, मुंबई में आयोजित वार्षिक दिवस कार्यक्रम के दौरान रेल अधिकारियों, सिविल डिफेन्स स्वयंसेवकों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को संबोधित करते हुए तथा औपचारिक परेड का निरीक्षण करते हुए; सिविल डिफेन्स के उपकरणों और साधनों की प्रदर्शनी।

पश्चिम रेलवे सिविल डिफेन्स संगठन द्वारा सिविल डिफेन्स वार्षिक दिवस का आयोजन गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2025 को पश्चिम रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड, महालक्ष्मी में किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा सिविल डिफेन्स ध्वज फहराया। उन्होंने उपस्थित रेल अधिकारियों, सिविल डिफेन्स स्वयंसेवकों, कर्मचारियों और उनके परिजनों को संबोधित किया तथा स्वयंसेवकों को सामुदायिक क्षमता–निर्माण एवं संकट की स्थिति में लोगों की सहायता हेतु निरंतर योगदान देने का आवाहन किया।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिम रेलवे, श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम की शुरुआत नौ टुकड़ियों की एक औपचारिक परेड से हुई, जिसमें एक सर्व–महिला टुकड़ी भी शामिल थी। इसके बाद सिविल डिफेन्स स्वयंसेवकों द्वारा विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों—जैसे हवाई हमले एवं बम विस्फोट—के दौरान अपनाई जाने वाली बचाव एवं राहत तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। कोच के अंदर लगी आग को बुझाने की प्रक्रिया प्रदर्शित करने हेतु फायर–बॉल का उपयोग करते हुए एक विशेष अग्निशमन ड्रिल भी आयोजित की गई। रेलवे परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने और ट्रेसपासिंग की रोकथाम के महत्व का संदेश देने के लिए एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर सिविल डिफेन्स उपकरणों, साधनों एवं तैयारियों को दर्शाती एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो पश्चिम रेलवे की मजबूत सिविल डिफेन्स क्षमताओं को प्रतिबिंबित करती है।

अपने संबोधन में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने सिविल डिफेन्स स्वयंसेवकों की निष्ठा, समर्पण एवं सेवाभाव की सराहना की तथा उन्हें सामुदायिक क्षमता–निर्माण और आपातकालीन सहायता में निरंतर योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति का संदेश भी पढ़ा गया। कार्यक्रम का आयोजन पश्चिम रेलवे के उप महाप्रबंधक (जी) एवं नियंत्रक, सिविल डिफेन्स, श्री उज्ज्वल देव के मार्गदर्शन में किया गया।

पश्चिम रेलवे सिविल डिफेन्स की तैयारियों को और अधिक सुदृढ़ करने तथा रेलवे नेटवर्क में सुरक्षा, लचीलापन एवं सामुदायिक सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि करता है।

पश्चिम रेलवे चलाएगी उर्स उत्सव के दौरान बांद्रा टर्मिनस और अजमेर के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा अजमेर उर्स उत्सव के दौरान यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान रखते हुए बांद्रा टर्मिनस–अजमेर स्टेशन के बीच विशेष किराए पर स्पेशल ट्रेन चलायी जाएगी। इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन संख्या 09063/09064 बांद्रा टर्मिनस – अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09063 बांद्रा टर्मिनस – अजमेर स्पेशल बुधवार, 24 दिसंबर, 2025 को 12:15 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 06:15 बजे अजमेर पहुंचेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09064 अजमेर – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल गुरुवार, 25 दिसंबर, 2025 को 11:40 बजे अजमेर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, नडियाद, साबरमती, महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, पिण्डवाड़ा, फालना, रानी, मारवाड़, सोजत रोड और ब्यावर स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में AC - 2 टियर, AC - 3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09063 के लिए बुकिंग 12 दिसंबर 2025 से सभी PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

बांग्लादेश चुनाव की दस्तक: विद्रोह के बाद बदलते राजनीतिक मौसम में पहली बड़ी परीक्षा

(जीएनएस)। ढाका की ठंडी शामों में चुनाव आयोग का एलान किसी तेज़ घंटी की तरह गूंज उठा। बांग्लादेश, जो पिछले बरसों में राजनीति, विद्रोह, संघर्ष और सत्ता परिवर्तन की उथल-पुथल से गुजर चुका है, अब एक बार फिर लोकतंत्र की ओर लौटने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद देश में होने वाला यह पहला आम चुनाव है, और शायद पिछले कई दशकों में सबसे अनिश्चित, सबसे अधिक चर्चा वाला और सबसे चुनौतीपूर्ण भी। 12 फरवरी 2026 की सुबह 12.70 करोड़ मतदाता 300 संसदीय सीटों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही ढाका से लेकर चिटगाँग, सिलेहट से लेकर खुलना तक की गलियों में चुनावी रंगत घुलने लगी है। वर्षों से एक ही सत्ता के हाथों में बंधी राजनीति अब एक नई राह पर है—जहां पुराने समीकरण टूट रहे हैं और नए चेहरें उभर रहे हैं। 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा, भारी जनाक्रोश और लगातार दबाव ने अंततः शेख हसीना को पद छोड़ने पर मजबूर किया था। उनके पदत्याग के बाद अवामी लीग पर चुनाव लड़ने से रोक लगा दी गई। यह वही अवामी लीग है जो दशकों से देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक

शक्ति रही है। लेकिन इस बार मैदान में वह नहीं है। वह खाली जगह, जो कभी अप्राप्य लगती थी, अब नए दलों और पुराने विरोधियों के लिए बड़ी संभावनाएं लेकर आई है।

इस बदलते राजनीतिक समुंदर में सबसे मजबूत नाव बनकर उभरी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी—बीएनपी। खालिदा जिया की खराब तबीयत और उनके बेटे तारिक रहमान का लंदन में निर्वासन में होना पार्टी की कमजोरी लग सकता है, लेकिन जनभावना कुछ और ही दिखा रही है। अमेरिकी इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के ताज़ा सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि बीएनपी सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है। देश का बांग्लादेशी राष्ट्रवाद, आर्थिक सुधारों की उम्मीदें और भ्रष्टाचार विरोधी वादों पर भरोसा अभी भी बीएनपी को एक बड़ा जनाधार देता है। लेकिन इस चुनावी वातावरण में सिर्फ बीएनपी ही कहानी का मुख्य पात्र नहीं है। वर्षों से प्रतिबंधित और राजनीतिक हाशिये पर खड़ी जमात-ए-इस्लामी अब फिर से सक्रिय हो गई है। छात्र विद्रोह की आग ने कई पुरानी परतों को उधेड़ा, और उन्हीं में से एक परत यह भी थी कि जमात फिर जमीन पर लौट आई। शफीकुर रहमान के नेतृत्व में यह पार्टी इस्लामी शासन की बात तो करती ही है, लेकिन इस बार उसने अपने रूढ़िवादी वोट बैंक से बाहर निकलने का प्रयास शुरू किया है। माफिया-मुक्त समाज, ईमानदार शासन और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई जैसे वादों ने उसे नए समर्थक दिए हैं। 2001 से 2006 तक बीएनपी के साथ सत्ता में रह चुकी यह पार्टी अब दोबारा अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है।

इस चुनाव की विशेषता यह भी है कि पहली बार देश का राजनीतिक परिदृश्य बिना अवामी लीग की छाया के बन रहा है। गांवों के चौक–चौराहों, कपड़ों की दुकानों, चाय के ढाबों और मस्जिदों के बाहर खड़े लोगों की चर्चाओं में भी यही सवाल गूंज रहा है—यह चुनाव बांग्लादेश को किस दिशा में ले जाएगा? यह नया नेतृत्व देश के लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था को स्थिर कर पाएगा या नहीं? 17.3 करोड़ की आबादी वाले इस राष्ट्र की उम्मीदें कई बार टूट चुकी हैं, लेकिन हर चुनाव के साथ एक नए सवेरा की चाह फिर जागती है।

12 फरवरी को लोग सिर्फ वोट नहीं डालेंगे—वे उस देश का भविष्य चुनेंगे जो विद्रोह की आग से निकलकर, अस्थिरता की धुंध को पार कर, एक नई राजनीतिक सुबह की तलाश में खड़ा है। यह चुनाव सत्ता का संघर्ष भर नहीं, बल्कि बांग्लादेश की नई पहचान गढ़ने की कोशिश है। यह कोशिश कितनी सफल होगी, यह समय ही बताएगा—पर इतना तय है कि इस चुनाव की गूंज सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में लंबे समय तक सुनाई देगी।

बहन की शादी में शामिल होने के लिए दो हफ्ते बाद जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद

(जीएनएस)। दिल्ली की सर्द हवा में अदालत के एक फैसले ने अचानक गर्माहट पैदा कर दी। 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी और लंबे समय से जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद को आखिरकार दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मिल गई है। पांच साल से अधिक समय तक बंद दरवाज़ों और अदालतों के बीच झूलती उनकी जिंदगी को पहली बार ऐसा मौका मिला है जब वह जेल की सलाखों के बाहर खुली हवा में अपने परिवार के बीच खड़े होंगे—वह भी अपनी सगी बहन की शादी के पावन अवसर पर।

दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने कहा कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रह सकेंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने अपने आदेश में साफ लिखा कि चूंकि यह शादी उनकी वास्तविक बहन की है और परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए अदालत मानवीय आधार पर जमानत आवेदन स्वीकार करती है। अदालत ने यह राहत 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतियों के आधार पर दी है।

लेकिन यह आज़ादी बिना शर्त नहीं है। जमानत की अवधि के दौरान खालिद किसी भी तरह का सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वह केवल अपने परिवार, रिश्तेदारों और नज़दीकी दोस्तों से मिल सकेंगे—वही लोग जो वर्षों से उनके लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। खालिद को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह केवल अपने घर पर रहें या उन्हीं स्थानों पर जाएं, जिन्हें उन्होंने शादी से जुड़े कार्यक्रमों के लिए अदालत को बताया है।

यह भी गौर करने योग्य है कि खालिद ने पहले 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की जमानत मांगी थी, क्योंकि 27 दिसंबर को उनकी बहन की शादी तय है। अदालत ने दो दिन के अंतर को छोड़कर उनका अनुरोध मान लिया।

सितंबर 2020 में गिरफ्तारी के बाद से खालिद अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों—आपराधिक साज़िश, दंगा, गैरकानूनी सभा और यूएपीए जैसी कठोर धाराओं के तहत मामले—का सामना कर रहे हैं। इन आरोपों ने उनकी जमानत की राह को हमेशा बेहद मुश्किल बनाए रखा। कई बार याचिकाएँ वापस ली गईं, कई बार अदालतों ने लंबी सुनवाई की, लेकिन इस बीच उनका परिवार सिर्फ उम्मीदों के सहारे ही जीता रहा।

अब, इतने वर्षों बाद उन्हें मिली यह छोटी-सी राहत एक परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। माँ–बाप की वह आँखें, जो हर अदालत की तारीख पर उम्मीद और थकावट के बीच टिमटिमाती रहती थीं, अब कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन चमक उठेंगी।

अपने पुराने बैंक खाते में पैसे जमा करके भूल गए?

जो आपका है उसे वापस दिलाने में आरबीआई आपकी मदद करेगा।

आपके बैंक के निष्क्रिय खाते (2 वर्ष से ज़्यादा और 10 वर्ष तक असक्रिय) में जमा पैसे / दावा न की गई जमा राशि (10 वर्ष से अधिक) को आरबीआई के डीईए फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप या आपके क़ानूनी वारिस उसे कभी भी वापस ले सकते हैं।

आपके पैसे वापस पाने के 3 आसान चरण

1. आपके बैंक की किसी भी शाखा में जाएं, भले ही वो आपकी नियमित शाखा न हो।
2. केवाईसी दस्तावेजों (आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस) के साथ फॉर्म जमा करें।
3. सत्यापन के बाद ब्याज समेत, यदि है तो, अपने पैसे वापस पाएं।

दावा न की गई संपत्ति के संबंध में आयोजित विशेष शिविरों में जाएं, जिसे देशभर के सभी ज़िलों में अक्तूबर से दिसंबर 2025 के बीच लगाए जाएँगे।

आपके दावा न किए गए पैसे के बारे में जानने के लिए

आपके बैंक की वेबसाइट पर खोजें या आरबीआई के UDGAM पोर्टल **(https://udgam.rbi.org.in)** पर देखें, जिसमें फ़िलहाल 30 बैंक शामिल हैं।

क्यूआर कोड स्कैन कीजिए

अधिक जानकारी के लिए
https://rbikehtahai.rbi.org.in देखिए
प्रतिक्रिया के लिए **rbikehtahai@rbi.org.in** पर लिखिए

आधिकारिक व्हॉट्सऐप नंबर
99990 41935

जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

3 साल
अडिग नेतृत्व और
अविरत विकास के

माननीय मुख्यमंत्री
श्री भूपेन्द्रभाई पटेल के
अडिग नेतृत्व और अविरत विकास के 3 वर्ष

करुणामय और कटिबद्ध

मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना के तहत **4 लाख से अधिक गर्भवती और धात्री माताओं को पोषण युक्त आहार की सुविधा**

PMJAY के अंतर्गत **₹10 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध**

नमो लक्ष्मी योजना अंतर्गत **10 लाख से अधिक छात्राओं को वित्तीय सहायता**

मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत **1 लाख से अधिक स्मार्ट क्लासरुम का निर्माण**

महिला सशक्तिकरण हेतु **200 से अधिक महिला-केंद्रित योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन**

मातृ मृत्यु दर में 50% और **बाल मृत्यु दर में 57%** की महत्वपूर्ण गिरावट

निर्भीक और निर्णायक

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाकर कई समस्याओं का समाधान

गुजरात की शांति व सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए **पुलिस भर्ती की घोषणा**

प्रोजेक्ट VISWAS के तहत गुजरात में **7,000 से अधिक CCTV कैमरों** का व्यापक नेटवर्क स्थापित

नीति आयोग की तर्ज पर गुजरात में थिंक टैंक **GRIT की स्थापना**

सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के लिए **हेल्पलाइन नंबर 112 की शुरुआत**

राजस्व कानूनों का **सरलीकरण**

9 नगरपालिकाओं को महानगरपालिका का दर्जा

ऊर्जावान और उद्यमशील

गुजरात को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी, राज्य में कई विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हुए विकसित, 24 स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स भी कार्यरत

गुजरात में स्थापित होने वाले **4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स** युवाओं को देंगे अपार रोजगार के अवसर

स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में **लगातार चार बार गुजरात बेस्ट परफ़ॉर्मर स्टेट**

UNESCO द्वारा **गरबा को 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' की मान्यता**

UNWTO द्वारा धोरडो को विश्व का **"सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव" घोषित**

जनजातीय गौरव दिवस पर **₹2 लाख करोड़ के बजट के साथ जनजातीय कल्याण योजना की शुरुआत**

"निर्णायकता और दूरदर्शिता के साथ गुजरात का सर्वांगीण विकास ही हमारा अटल संकल्प है।"

- श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात